राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने बारे

24 श्री लक्ष्मण नापा (रतिया) :

क्या मुख्यमंत्री कृप्या बताएंगे कि–

(क) क्या यह तथ्य है कि रतिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रतिया शहर में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए सरकार द्वारा 5 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी थी लेकिन अब तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ; तथा

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य के कब तक आरम्भ होने की संभावना है?

उत्तर श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा

श्रीमान जी,

क) रतिया शहर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की कोई भी स्वीकृति जारी नहीं की गई है यद्यपि रतिया विधान सभा क्षेत्र के गांव जाखनदादी जिला फतेहाबाद में प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत नई आई.टी.आई. खोलने का प्रस्ताव है जिसके भवन निर्माण के लिए 40 कनाल भूमि की स्वीकृति दिनांक 30.01.2019 को दी जा चुकी है। भारत सरकार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 502.00 लाख रूपये की स्वीकृति प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2015-16 में प्रदान की गई थी। यद्यपि यह राशि पर्याप्त नहीं थी इसलिए 1581.68 लाख रूपये का नया प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय को दिनांक 13.12.2022 को भेजा जा चुका है। उनकी स्वीकृति अभी लम्बित है।

ख) यह भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करने पर निर्भर है।

To Open an ITI

24 Sh. LAKSHAMAN NAPA (Ratia):

Will the **Chief Minister** be pleased to state that:-:-

a) whether it is a fact that an amount of Rs. 5 crores was sanctioned by the Government to open an ITI in Ratia City of Ratia Assembly Constituency but the work has not been started so far;and

b) if so, the time by which the said work is likely to be started?

Answer Sh. Manohar lal, Chief Minister, Haryana

Sir,

a) There is no approval for opening of Govt. ITI in Ratia city. However there is a proposal under Pardhan Mantri Jan Vikas Karyakram to open a new Govt. ITI in Village Jakhan-Dadi in Ratia AssemblyConstituency of District Fatehabad. 40 Kanal Land has been transferred already on 30.1.2019 for construction of a building. Ministry of Minority Affairs, Govt. of India approved Rs. 502.00 lakhs in the financial year 2015-16 under Pardhan Mantri Jan Vikas Karyakram. However this amount was insufficient, so a new proposal of Rs.1581.68 lakhs has been sent to the Ministry of Minority Affairs on 13.12.2022. Their approval is pending.

b) It depends upon approval to be given by the Govt. of India.